

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.4567  
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी ब्रॉडबैंड

**4567. श्री जयन्त बसुमतारी:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जून 2025 तक पूर्वोत्तर भारत में 4जी या ब्रॉडबैंड सेवाओं से असंबद्ध रहे गए गांवों की राज्य-वार संख्या का व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दूरसंचार विभाग या सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के साथ सहयोग किया है;
- (ग) पूर्वोत्तर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति क्या है; और
- (घ) दूरस्थ और सीमावर्ती ज़िलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-गवर्नेंस हेतु डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के 45,934 गांवों में से (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार), 42,093 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है और इनमें से 40,663 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में मोबाइल कवरेज की राज्य-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

सेवा से वंचित किसी भी बसे हुए गांव के लिए मोबाइल कवरेज तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से प्राप्त वित्त पोषण के माध्यम से एनईआर सहित देश के ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों को लागू कर रही है।

एनईआर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) के तहत डीबीएन परियोजनाएं क्षेत्र की अल्पसेवित आबादी तक मोबाइल नेटवर्क पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से सेवा से वंचित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हैं। जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार एनईआर में डीबीएन स्कीमों के अंतर्गत 2,485 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं, जिसमें 3,389 गांवों/स्थानों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश में सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख बिना ग्राम पंचायतों वाले गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार 6,355 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है और एनईआर में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 12,283 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

डीबीएन परियोजनाओं के तहत प्रदान की गई दूरसंचार कनेक्टिविटी ने दूरस्थ और सीमावर्ती जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ई-गवर्नेंस के लिए संचार और डिजिटल सेवाओं की समान पहुंच प्रदान की है।

### अनुबंध

"पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी ब्रॉडबैंड" के संबंध में माननीय सांसद द्वारा पूछे गए 20 अगस्त, 2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राज्य-वार मोबाइल कवरेज की स्थिति

राज्य	गांवों की कुल संख्या (आरजीआई आंकड़ों के अनुसार)	मोबाइल कनेक्टिविटी वाले गांवों की संख्या	4जी कवरेज वाले गांवों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	5993	4258	3094
असम	26429	26007	25934
मणिपुर	2612	2219	2132
मेघालय	7100	6424	6394
मिजोरम	867	755	749
नागालैंड	1535	1235	1213
सिक्किम	461	453	442
त्रिपुरा	937	742	705
<b>कुल</b>	<b>45,934</b>	<b>42,093</b>	<b>40,663</b>

\*\*\*\*\*